बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 298

असल रोजगार का संकट

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के दो वरिष्ठ सदस्यों के इस्तीफा देने के एक दिन बाद गुरुवार को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी रही, जो 45 साल में सबसे अधिक है। आयोग के सदस्यों का आरोप था कि सरकार ने देश में बेरोजगारी की स्थिति पर एक सर्वेक्षण जारी करने से रोक दिया है।

युवाओं में बेरोजगारी की दर पिछले वर्षों की तुलना में काफी ऊंचे स्तर पर थी। रिपोर्ट में कहा गया है, 'कुल आबादी की तुलना में काफी अधिक।' उदाहरण के लिए 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी की दर 2017-18 में 17.4 फीसदी पर पहुंच गई, जो 2011-12 में 5 फीसदी थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में युवा महिलाओं में बेरोजगारी की दर वर्ष 2017-18 में 13.6 फीसदी थी। यह 2011-12 में 4.8 फीसदी थी। शहरी इलाकों में स्थिति और विकराल हुई है, जहां पुरुषों में बेरोजगारी की दर 18.7 फीसदी और महिलाओं में 27.2 फीसदी रही। रोजगार की दर के मामले में भारत विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से एक है। रोजगार की दर में भारी गिरावट वास्तविक संकट को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि अगर लोग श्रम बल में शामिल नहीं हैं तो भारत की विशाल आबादी का कोई फायदा नहीं है। एनएसएसओ ने पहली बार पीएलएफएस किया है, जो बेरोजगारी को मापने वाला सालाना सर्वेक्षण है। इससे पहले एनएसएसओ पांच साल में सर्वेक्षण करता था। सरकार ने इस सर्वेक्षण को समाप्त कर पीएलएफएस को चुना था। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि सालाना सर्वेक्षण से बेरोजगारी पर बारीक नजर रखी जा सकती है। इतना ही नहीं, पांच वर्ष के सर्वेक्षण एक या दो साल की देरी से आते थे, जिससे उनका समय पर विश्लेषण नहीं हो पाता था।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि यह महज एक प्रारूप रिपोर्ट है और इसे जारी करने से पहले और काम करना जरूरी है। लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि अवधि में बदलाव के बावजूद पीएलएफएस में इस्तेमाल की गई बेरोजगारी की अवधारणा वही है, जो पिछले सभी पंचवर्षीय सर्वेक्षणों में थी। यही वजह यह है कि प्रारूप रिपोर्ट में पीएलएफएस और सभी पंचवर्षीय दौरों की बेरोजगारी की दर 1972-73 तक दी गई हैं।

शहरी और ग्रामीण पुरुषों तथा महिलाओं में सामान्य स्थिति (मुख्य स्थिति + सहायक स्थिति) पर आधारित बेरोजगारी की दर दर्शाती है कि 2017-18 में इसमें अचानक बढ़ोतरी हुई है। यह सही है कि पूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह साफ नहीं है कि क्या नमूने के आकार और नमूने के डिजाइन जैसे पद्धति कारकों से तुलना करने की क्षमता कम हो गई है। उदाहरण के लिए पंचवर्षीय ईयूएस में पूरे देश का एक नमूना होता था, जिसमें एक लाख परिवार शामिल होते थे। पीएलएफएस एक सालाना सर्वेक्षण है, इसलिए संभव है कि इसमें नमूना छोटा रखा गया हो। वास्तव में आधिकारिक वेबसाइट से यह पता चलता है कि पीएलएफएस में दो अलग-अलग नमूने होंगे। एक ग्रामीण और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। इन नमूनों को अलग-अलग समय पर अद्यतन बनाया जाएगा।

सरकार एनएसएसओ के सर्वेक्षण के प्रकाशन को रोक रही है, लेकिन यह बाहर आ रहा है। यह भारत में बेरोजगारी की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। इस सर्वेक्षण में डेटा के संग्रहण का काम जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच किया गया। इसलिए ये नतीजे अहम है क्योंकि ये उन सबूतों की पुष्टि करते हैं कि नवंबर 2016 में नोटबंदी की वजह से आर्थिक गतिविधियां बड़े स्तर पर प्रभावित हुई थीं। केवल ऐसा नहीं है कि 2017-18 में बेरोजगारी का स्तर ऊंचा था, बल्कि बेरोजगारी में भी भारी बढ़ोतरी हुई।

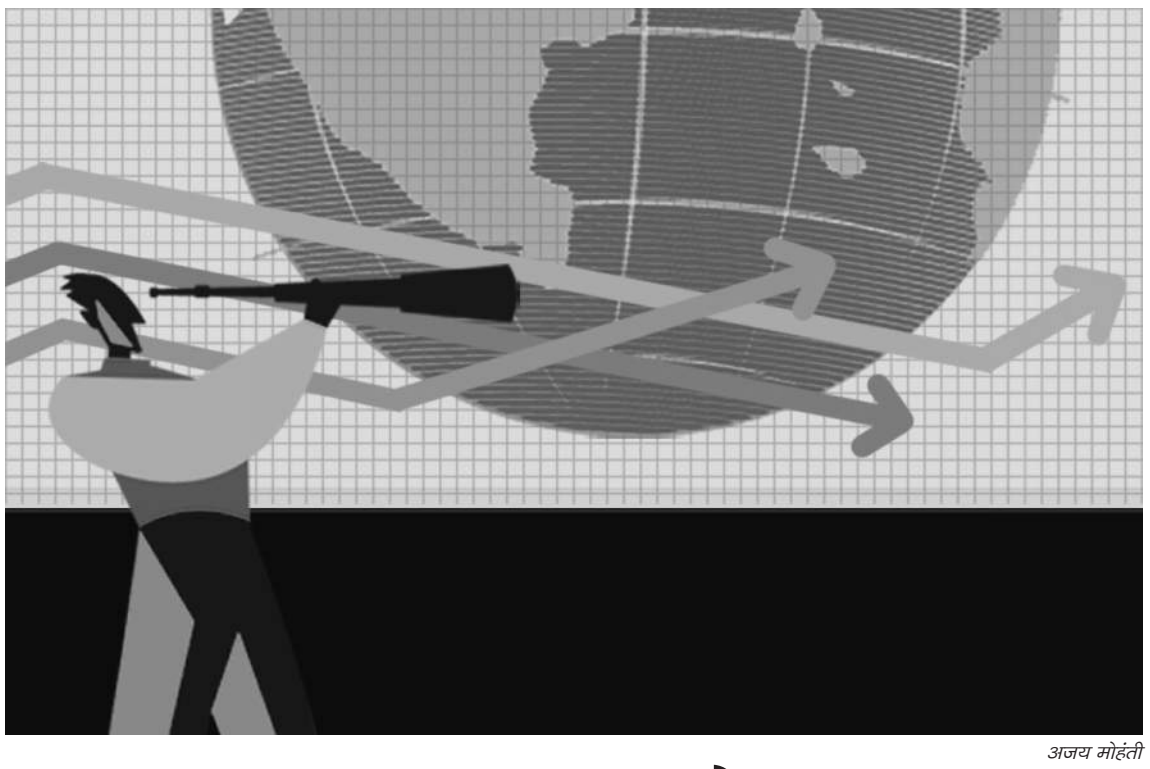

अजय मोहंती

दीर्घकालिक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

भारत को जननांकीय लाभांश का फायदा मिलना तय है जबकि चीन के प्रदर्शन में काफी धीमापन आ सकता है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **आकाश प्रकाश**

अत्यंत प्रतिष्ठित और स्वतंत्र आर्थिक शोध करने वाली सलाहकार संस्था कैपिटल इकनॉमिक्स ने हाल ही में आगामी 20 वर्षों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अपने अनुमान जाहिर किए। इनमें समग्र विश्व अर्थव्यवस्था, उभरते बाजारों और भारत समेत 10 प्रमुख देशों के लिए जताए गए अनुमान शामिल हैं। ये अनुमान दिलचस्प हैं क्योंकि वे इस आम धारणा को नहीं मानते कि भविष्य चीन का है। इसके उलट उनका दांव अमेरिका और भारत पर है। इसकी वजह जरूर अलग-अलग हैं।

उनके अध्ययन के कुछ दिलचस्प नतीजे इस प्रकार हैं:

■ आगामी 20 वर्ष में (2040 तक) वैश्विक जीडीपी की औसत वृद्धि दर करीब 3 फीसदी रहेगी जबकि बीते 20 वर्ष में यह तकरीबन 3.5 फीसदी रही है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) विनिमय दर के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था 80 प्रतिशत तक विकसित होगी। पश्चिम के विकसित देशों का जीडीपी करीब 50 फीसदी बढ़ेगा जबकि उभरते बाजारों में 100 फीसदी बढ़ोतरी होगी। सन 2040 तक उभरते बाजार विश्व अर्थव्यवस्था के 70 फीसदी के लिए जिम्मेदार होंगे जबकि आज यह स्तर केवल 60 फीसदी है। वैश्विक वृद्धि में इनका योगदान 80 फीसदी होगा।

■ उभरते बाजार समग्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान रखेंगे लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनके आर्थिक प्रदर्शन में काफी अंतर होगा। चीन सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था होगा लेकिन आगामी 20 वर्ष में उसमें काफी मंदी आएगी। कैपिटल इकनॉमिक्स के मुताबिक चीन को कई ढांचागत चुनौतियों का सामना करना होगा। उसकी कामगार आबादी अगले 20 साल में 12 फीसदी कम होगी और पूंजी संग्रह में कमी आएगी। देश में प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक पूंजी शेयर का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। वहां ढांचागत सुधारों को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिख रही जबकि इससे पूंजी आवंटन में सुधार हो सकता है, सरकार की भूमिका कम हो सकती है और इस प्रकार उत्पादकता में इजाफा हो सकता है। अनुमान यह भी है कि चीन की स्थायी विकास दर उक्त अवधि में गिरकर करीब 2 फीसदी रह जाएगी जबकि फिलहाल यह 6 फीसदी है। कामगार उम्र वाले श्रमिकों की आबादी में कमी और उत्पादकता में सुधार कम होगा। ऐसे में वृद्धि दर में कमी आनी तय है। अध्ययन के मुताबिक वैश्विक जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी मौजूदा 19 फीसदी से गिरकर 2040 तक 17 फीसदी रह जाएगी। यह बात मौजूदा समझ के विपरीत है। अधिकांश जगह मौजूदा सदी को चीन की सदी बताया जा रहा है। आगामी 20 वर्ष में चीन के प्रति व्यक्ति जीडीपी में 70 फीसदी का इजाफा, बीते 20 वर्ष में हुए पांच गुना इजाफे से काफी कम है। अध्ययन के मुताबिक चीन के लिए प्रतिव्यक्ति जीडीपी अमेरिका के स्तर के एक तिहाई होगा।

भारत को लेकर इसके अनुमान और उत्साहजनक हैं। लेखकों का अनुमान है कि अगले 20 वर्ष में भारत 5 से 7 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करेगा। यह अन्य देशों के मुकाबले बहुत ऊंची दर होगी। इन अनुमानों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार तीन गुना हो जाएगा और जीडीपी पीपीपी आधार पर आज के 8 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी पहुंच जाएगी। बाजार विनिमय दर पर भी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका के 10 फीसदी के स्तर से सुधरकर 25 फीसदी हो जाएगा। यह उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे अधिक स्तर होगा।

देश की वृद्धि को लेकर यह सकारात्मकता कामगार उम्र की आबादी में इजाफे से है। वर्ष 2025 तक भारत श्रम शक्ति आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा। उत्पादकता को लेकर भी सकारात्मक अनुमान हैं। भारत के पूंजी बाजार में गहराई आ रही है और उसके श्रमिक उच्च उत्पादकता वाले रोजगार अपना रहे हैं। धीमे ढांचागत सुधार प्रक्रियाधीन हैं और ये पूंजी आवंटन और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में सुधार करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सभी उभरते बाजारों के बीच शानदार प्रदर्शन करने वाला देश होगा।

■ रिपोर्ट अमेरिका को लेकर भी सकारात्मक है। लेखकों का अनुमान है कि तमाम विकसित देशों में उत्पादकता बढ़ेगी लेकिन अमेरिका शीर्ष पर होगा। कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स जैसी नई तकनीक श्रम की उत्पादकता पर व्यापक असर डालेंगी। अपने खुले और प्रतिस्पर्धी श्रम और उत्पाद बाजारों की बदौलत अमेरिका बढ़त बनाएगा। यह बढ़त बढ़ती उम्र वाली आबादी की कमी की भरपाई करेगी।

वर्ष 2005 से ही अमेरिका में उत्पादकता वृद्धि में धीमापन आया है और यह बमुश्किल एक फीसदी रह गई है। सन 1990 के दशक के मध्य में यह दर 2.3 फीसदी थी। रिपोर्ट में लेखकों ने कहा है कि अमेरिकी उत्पादकता एक बार फिर बढ़ेगी और यह 2030 तक 2 फीसदी हो सकती है।

उत्पादकता में वृद्धि से अमेरिकी जीडीपी वृद्धि को गति मिलेगी और वह 1.5 फीसदी से बढ़कर 2030 तक 2.6 फीसदी हो सकती है। अमेरिका में इस स्तर पर सुधार की उम्मीद किसी को नहीं है। कैपिटल इकनॉमिक्स का अनुमान है कि यह वृद्धि नई तकनीक को अपनाने के कारण आ सकती है। उनका कहना है कि वृद्धि दर के मामले में 2030 तक अमेरिका, चीन से आगे निकल जाएगा। यह बात फिलहाल पर्याप्त विवाद पैदा कर सकती है।

अगर उनके अनुमान सही हैं तो न केवल अमेरिका प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दुनिया का सबसे अमीर देश बना रहेगा बल्कि अन्य विकसित देशों के साथ उसका अंतर भी बढ़ेगा।

यूरोक्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो इटली को लेकर अत्यंत नकारात्मक अनुमान जताए गए हैं। यूरोप में उसका जननांकीय प्रोफाइल सबसे खराब है और उत्पादकता के मामले में भी उसका प्रदर्शन कोई खास नहीं। इसकी अर्थव्यवस्था ठहरी रहेगी और पूरे यूरो क्षेत्र के लिए समस्या बनेगी। फ्रांस और जर्मनी में उत्पादकता वृद्धि सुधरेगी।

ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो दीर्घावधि में भारत के लिए सकारात्मक बात सहज सुस्पष्ट लगती है। देश का जननांकीय ढांचा सही है, उत्पादकता के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं में उद्यमिता और आकांक्षा बढ़ रही है। ढांचागत सुधारों की बात करें तो धीमे होने के बावजूद इनको अंजाम दिया गया है। आर्थिक वृद्धि और कारोबारी आय में भी गति आनी चाहिए। अगले कुछ दशकों में आगे बढ़ते हुए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आगामी चुनाव में राजनीतिक दल कई आर्थिक वादे करेंगे। तमाम दल कई लोकलुभावन वादे कर सकते हैं। हमेशा की तरह निवेशकों को जुबान पर नहीं बल्कि वास्तविक कदमों पर ध्यान देना होगा। तमाम निवेशकों को देश की लंबी अवधि की संभावनाओं पर ध्यान देना होगा, न कि आगामी चुनाव से जुड़ी नारेबाजी पर।

सोशल मीडिया मंचों के लिए परीक्षा की घड़ी होंगे चुनाव

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

फेसबुक, गूगल और ट्विटर राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने के लिए नए उपाय अपना रहे हैं। ऐसे में आगामी आम चुनाव के दौरान भारत इस परीक्षण के लिहाज से अहम होगा।

ये तीनों वैश्विक स्तर पर समाचार प्रसारित करने वाले सबसे बड़े मंच हैं। कम से कम 200 करोड़ लोग समाचार प्राप्ति के प्राथमिक माध्यम के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन विज्ञापन के क्षेत्र में भी इनका बहुत तगड़ा दखल है। गूगल और फेसबुक के पास कुछ खास क्षेत्रों में जबरदस्त बाजार हिस्सेदारी है जबकि ट्विटर तीसरे स्थान पर है। गूगल के पास यूट्यूब के रूप में वीडियो सामग्री का एक बड़ा मंच है और फेसबुक के पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप हैं।

वर्ष 2008 में बराक ओबामा ने जब पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था तब वह सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल का शुरुआती उदाहरण था। वर्ष 2016 में उस समय विवाद उत्पन्न हुआ जब ब्रेक्सिट अभियान (जून 2016) सफल हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई। उक्त दोनों अभियानों के दौरान सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग (ऑनलाइन गलतबयानी, गाली गलौज आदि करने वाले) करने वालों ने गलत सूचनाएं फैलाईं और वोटिंग के रुख को प्रभावित करने में सफल रहे। इसी अवधि में कैंब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के निजी यूजर डेटा तक पहुंच बनाई।

वर्ष 2019 में सभी राजनीतिक समूह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इस्तेमाल काफी हद तक वैध भी है। परंतु सोशल मीडिया नेटवर्क फेक न्यूज (झूठी खबरों) के भी प्रमुख वाहक हैं। ये झूठी खबरें जनमत बदलने के लिए प्रसारित की जाती हैं। फेसबुक फरवरी में भारत को लेकर खास उपाय जारी करने जा रहा है। इनमें पहला कदम है बेनामी रहने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना। कंपनी ने अपने विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों से कहा है कि वे अपने पते और पहचान के दस्तावेज की स्कैन कॉपी मुहैया कराएं जिनका प्रमाणन फेसबुक करेगा। फेसबुक ने राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ भी एक दिशानिर्देश साझा किया है। इसमें सभी सांसद, मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी शामिल हैं। राजनीतिक विज्ञापनों को राजनीतिक व्यक्तित्वों, पार्टियों, चुनावों और विधानों के रूप में अलग-अलग संदर्भित किया जाएगा। राजनीतिक विषयवस्तु वाले पन्नों के एडमिनिस्ट्रेटरों और राजनीतिक विज्ञापकों को प्रमाणिम पहचान और अपने काम करने की जगह बतानी होगी। भारत के बाहर से आने वाली सामग्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

राजनीतिक विज्ञापनदाताओं से कहा जाएगा कि वे अपनी विषयवस्तु और सामग्री के बारे में कहीं अधिक ब्योरा मुहैया कराएं। उनसे भुगतान का ब्योरा भी मांगा जाएगा। फेसबुक इन मामलों में चुनाव आयोग के मानकों का पालन करेगी। इसके तहत मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार अभियान बंद होने पर फेसबुक पर भी सामग्री को अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

इसके लिए फेसबुक न्यूजफीड को चलाने वाले अल्गोरिद्म में बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक दल एक कमी का फायदा उठाते हैं। वह यह कि फेसबुक न्यूजफीड की टाइमलाइन क्रमबद्ध नहीं है। राजनीतिक दल सामग्री अवरुद्ध करने के ऐन पहले उस सामग्री की भरमार कर देते हैं। इससे होता यह है कि बाद में बंदी के समय भी यह सामग्री फेसबुक पर नजर आती रहती है क्योंकि इसकी तादाद में इजाफा हो चुका होता है।

सभी विज्ञापनों में यह जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी कि उसके लिए भुगतान किसने किया है। उपयोगकर्ता चाहें तो किसी भी ऐसे विज्ञापन को रिपोर्ट कर सकते हैं जिसमें यह जानकारी न दी गई हो। ऐसे में फेसबुक तत्काल कार्रवाई करेगा।

हर प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों को एक ऐसी ऑनलाइन लाइब्रेरी में रखा जाएगा जिसे आसानी से तलाश किया जा सके। वहां विज्ञापन खरीदने वालों की पूरी जानकारी नियामकीय प्रमाणपत्रों आदि के साथ मौजूद रहेगी। ऐसी तमाम जानकारी को कम से कम सात वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन में यह व्यवस्था पहले से लागू है। वहां का उदाहरण लें तो इसमें विज्ञापन का बजट, दर्शकों की संख्या और उम्र, लिंग और दर्शकों के स्थान की जानकारी होगी।

गूगल भी ऐसे ही मिलते जुलते उपाय अपनाने पर विचार कर रहा है। गूगल ने तो अमेरिका में राजनीतिक विज्ञापनों का एक ऐसा आर्काइव बना भी लिया है जिसमें खोज की जा सकती है। इन आर्काइव में प्रत्याशी के नाम, विज्ञापनदाता, लागत, समयसीमा, दर्शकों आदि का डेटा आसानी से तलाश किया जा सकता है। भारत में भी वह ऐसा ही एक आर्काइव तैयार करने का प्रयास कर रही है। उसका इरादा आईडी के प्रमाणन शुरू करने का है। उसके विज्ञापनों में भी लेबल लगाकर जानकारी दी जाएगी कि वे भुगतान वाले विज्ञापन हैं। वह भारत के लिए खासतौर पर राजनीतिक विज्ञापनों की पारदर्शिता संबंधी रिपोर्ट तैयार करेगी।

ट्विटर का कहना है कि वह राजनीतिक दलों के खर्च की जानकारी वाला नया डैशबोर्ड प्रस्तुत करेगा। वह चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह तय करेगा कि विज्ञापनदाताओं की पहचान सुनिश्चित हो।

अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले चुनाव में ही ऑनलाइन विज्ञापन में 100-120 प्रतिशत उछाल आएगी। राजनीतिक विज्ञापनों की राशि के 12,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाने की उम्मीद है। गत वर्ष कुल ऑनलाइन विज्ञापनों पर 11,000 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे।

ये कंपनियां फेक न्यूज खत्म करने के लिए सलाहकारों के साथ काम पर लग चुकी हैं। ये मंच राजस्व के इतने बड़े स्रोत को गंवाना नहीं चाहेंगे लेकिन साथ ही उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों और आईटी नियमों में प्रस्तावित नए प्रतिबंधों का भय भी होगा।

कानाफूसी

अनुमति नहीं

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के उस फैसले को रद्द करने का निर्णय लिया है जिसके तहत प्रदेश की राजधानी के पास एक गोल्फ कोर्स बनाने का प्रस्ताव था। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गायों की चराई के लिए प्रयोग में लाई जा रही 100 एकड़ जमीन का चयन किया था। उस समय विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि वह चौहान के करीबी अफसरशाहों के लिए चरागाह की जमीन पर गोल्फ कोर्स बना रही है। अब राज्य के पशुपालन मंत्री लखन सिंह ने यह कहते हुए पूर्व सरकार का फैसला पलट दिया है कि वे राज्य के पशुपालन विभाग को चरागाह की जमीन किसी दूसरे कार्य में उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद से ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कामकाज की

शुभ अवसर की तलाश

तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं? खबर है कि सरकार बनने के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद के चंद्रशेखर राव अपनी टीम का विस्तार करने के लिए किसी शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केसीआर ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। वह केवल फरवरी में टीम विस्तार पर काम करेंगे। तेलुगु कैलेंडर के अनुसार 5 फरवरी को माघ महीने में प्रवेश होगा और अगले 5 दिन किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अच्छे होंगे। पर्यवेक्षकों का कहना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार की घोषणा 10 फरवरी या वसंत पंचमी को की जा सकती है। इस दिन पूरे देश में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है।

आपका पक्ष

अंतरिम बजट और बेरोजगारी की मार

शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं इसलिए सरकार के पास समय कम होने के कारण अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। केंद्रीय बजट या पूर्ण बजट के लिए सरकार के पास कम से कम एक साल का समय होना जरूरी है। सरकार अंतरिम बजट को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ढाल सकती है जिससे उन्हें इसका चुनावी लाभ मिल सके। हालांकि अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष कर संबंधी घोषणा नहीं की जा सकती है। प्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव केंद्रीय बजट में ही किया जा सकता है। अगर अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष कर को बढ़ाया जाता है तो इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की जरूरत होगी। सरकार बजट में अलग-अलग वर्गों को देखते हुए कई घोषणाएं कर सकती हैं।

चुनावी साल होने के कारण घोषणाएं बढ़ भी सकती हैं जिससे सत्तारूढ़ दल को इसका फायदा मिल सके। बहरहाल सरकार को सिर्फ चुनावी लक्ष्य नहीं देखना चाहिए। अभी हाल में सरकार ने गरीब सवर्ण को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है जिसे सरकार को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शिक्षा प्राप्त कर जब युवा नौकरी की तलाश करते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर युवा चपरासी की नौकरी के लिए भी आवेदन करते दिख जाते हैं। ऐसी कई खबरें मीडिया में आ चुकी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में रिक्तियां नहीं निकली हैं। कई सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को समाप्त कर दिया गया है। देश की एक बड़ी आबादी बेरोजगारी के दिन काट रहे हैं। आज गांव-देहात, कस्बे तथा शहरों में ठेले-खोमचे पर खाद्य सामग्री बेचने वालों की बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार को रोजगार सृजन करने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए।

सरकार को देश से बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नई नीति की घोषणा करनी चाहिए

किशोर कुमार, नोएडा

कमजोर तबके को आरक्षण जरूरी

समाज के कमजोर तबकों के लिए आरक्षण की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इश दिशा में सवर्ण को प्राप्त यह अधिकार उनकी सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए उतना ही अहम है जितना एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग को मिला हुआ है। संविधान लागू होने से अब तक आरक्षण का कोटा बढ़ता गया है। हालांकि संविधान में आरक्षण की समय सीमा 10 वर्ष के लिए ही लागू थी। समय-समय पर सत्ता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह वोट बैंक का रूप ले लिया। आरक्षण का लाभ जो जातियां उठा पाईं और समृद्ध हो गईं उन्हें पुश्त दर पुश्त लाभ मिलता रही। कई जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से बदहाल रही। आज आरक्षण की मांग राजनीतिक औजार बन गया है। मौजूदा सरकार द्वारा गरीब सवर्ण आरक्षण लागू किया जाना वोट बैंक की राजनीति है या वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा सुधारने के लिए उठाया गया कदम है, यह वक्त आने पर पता चलेगा।

शैलेंद्र कुमार, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।